



वर्ष-21, जम्मू तवी, अंक-311

नशीली दवाओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया

टिम साउदी करेंगे आईएलटी 20 के तीसरे संस्करण में शारजाह वारियर्स की कप्तानी

फसलों पर अनुकूल एवं प्रतिकूल मौसम का प्रभाव



मौसम जम्मू अधिकतम 17



E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात सन्देश



जम्मू तवी, शनिवार 28 दिसम्बर, 2024

मूल्य-3 रुपये- (लेह)4 रुपये

पृष्ठ - 8

डॉ सिंह का जीवन विपरीत परिस्थितियों में ऊंचाई हासिल करने की प्रेरणा देता है: मोदी

नयी दिल्ली 27 दिसम्बर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का जीवन आने वाली पीढ़ियों को विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर महान ऊंचाइयों को हासिल करने की प्रेरणा देता है।

डॉ सिंह का गुरुवार रात यहां एम्स में निधन हो गया था।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने यहां बताया कि श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह का निधन देश के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा, फ़जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है और विभाजन के दौरान भारत आने के बाद बहुत कुछ खोने के बावजूद डॉ. सिंह बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति थे। डॉ. सिंह का जीवन आने वाली पीढ़ियों को



सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों से कैसे ऊपर उठकर महान ऊंचाइयों को हासिल किया जाए। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि डॉ. सिंह को हमेशा एक दयालु व्यक्ति, एक विद्वान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने केन्द्र सरकार में डॉ. सिंह के एक अर्थशास्त्री के रूप में विभिन्न स्तरों पर अनगिनत योगदानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में डॉ. सिंह की भूमिका की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व

प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉ. सिंह ने देश को वित्तीय संकट से निकालकर नये आर्थिक रास्ते पर चलाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास और प्रगति में डॉ. सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों और देश के विकास के प्रति डॉ. सिंह की प्रतिबद्धता को हमेशा उच्च सम्मान में रखा गया है। श्री मोदी ने कहा कि डॉ. सिंह का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह का प्रतिष्ठित संसदीय करियर उनकी विनम्रता, सौम्यता और बुद्धिमत्ता से चिह्नित था। प्रधानमंत्री ने याद किया कि इस वर्ष की शुरुआत में राज्यसभा में डॉ. सिंह के कार्यकाल के अंत में भी, उन्होंने सभी के लिए प्रेरणा के रूप में डॉ. सिंह के समर्पण की प्रशंसा

की थी। अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद, डॉ. सिंह ने अपने संसदीय कर्तव्यों को पूरा करते हुए व्हीलचेयर पर महत्वपूर्ण सत्रों में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने और शीर्ष सरकारी पदों पर रहने के बावजूद, डॉ. सिंह अपनी साधारण पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि डॉ. सिंह हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के लोगों से संपर्क बनाए रखते थे और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध रहते थे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान और बाद में दिल्ली में डॉ. सिंह के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी खुली चर्चा को याद किया। उन्होंने डॉ. सिंह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और सभी नागरिकों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

जम्मू-कश्मीर में 117.58 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक कृषि परियोजनाओं को मंजूरी: जावेद डार

जम्मू 27 दिसंबर। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में कृषि अवसंरचना निर्माण के लिए 117.58 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

मंत्री ने एपीडी सचिव शैलेंद्र कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन और सीएडीडब्ल्यूएम के तहत इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मंजूरी सतत कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं न केवल कृषि अवसंरचना में सुधार करेंगी, सिंचाई दक्षता बढ़ाएंगी बल्कि जम्मू-कश्मीर में टिकाऊ कृषि परिस्थितिकी तंत्र भी सुनिश्चित करेंगी।

उन्होंने कहा कि विकास कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण को बढ़ावा देगा और किसानों और अन्य हितधारकों के लिए उत्पादकता और आर्थिक संभावनाओं में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।



उन्होंने कहा कि नाबाई के तहत स्वीकृत अन्य प्रमुख परियोजनाओं में पशुपालन की 12 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें ग्यारह पशु चिकित्सा अस्पतालों और एक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण और उन्नयन शामिल है, जिसके लिए 4067.04 लाख रुपये का स्वीकृत बजट है। परियोजनाओं में बांदीपुरा, गांदरबल और अर्न्तनागा में जिला पशु चिकित्सा अस्पतालों के निर्माण के अलावा किश्तवाड़, भद्रवाह, सांबा, कटुआ, गुज्जर कॉलोनी जम्मू और कालाकोट, परगवाल जिलों में जिला पशु चिकित्सा अस्पतालों का उन्नयन शामिल है। श्रीनगर में पेंरा-वट

ट्रेनिंग डेवलपमेंट शाल्टेरा का निर्माण भी पशुपालन क्षेत्र में स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में से एक है।

मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में 3051.65 लाख रुपये की लागत से शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विध्वविद्यालय जम्मू और शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विध्वविद्यालय कश्मीर में अत्याधुनिक छात्रावासों सहित अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के विकास को भी मंजूरी दी गई है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट में बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न जिलों में 4639.31 लाख रुपये

की लागत से 14 सीएडी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जो सिंचाई और फ़ैल्ड चैनलों के पुनरुद्धार पर केंद्रित हैं। इन परियोजनाओं में उधमपुर में बारहमासी प्राकृतिक जल स्रोतों का दोहन, कटुआ, बारामुला और अन्य जिलों में फ़ैल्ड चैनलों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, कुलगाम, पुलवामा और श्रीनगर में मौजूदा सिंचाई प्रणालियों का पुनर्वास भी शामिल है।

सहकारिता एवं चुनाव विभाग के मंत्री जावेद डार ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार, सिंचाई दक्षता में वृद्धि, तथा प्रशिक्षण, पशु चिकित्सा देखभाल और संसाधन प्रबंधन के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ किसानों को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने संबंधितों को समय पर कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने और परियोजनाओं को जल्द से जल्द जनता को समर्पित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें आवश्यकतानुसार श्रौत्र निष्पादन के प्रावधान भी शामिल हैं।

सीमा पार से अवैध गतिविधियों में शामिल तीन आतंकवादियों की संपत्तियां जब्त

राजौरी 27 दिसंबर। पुलिस ने शुक्रवार को सीमा पार से अवैध गतिविधियों में शामिल तीन आतंकवादियों की संपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन कंडी में दर्ज एक मामले के में आपराधिक प्रक्रिया सहिता (सीआरपीसी) की धारा 88 के तहत की गई है। जब्त की गई कुल संपत्ति 07 कनाल और 15 मरला है, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 18.5 लाख रुपये है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि कंडी तहसील कोटरका जिला राजौरी निवासी खादिम हुसैन पुत्र दिल मोहम्मद की 03 कनाल, 04 मरला और 31 वर्ग फीट, गखरोटे तहसील कोटरका जिला राजौरी निवासी मुनीर हुसैन पुत्र सईद की 02 कनाल और 08 मरला और पंजनारा, तहसील कोटरका जिला राजौरी निवासी मोहम्मद शबीर पुत्र फकीर मोहम्मद की 02 कनाल, 02 मरला और 253 वर्ग फीट जमीन जब्त की गई है। अधिकारियों ने कहा कि यह जब्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी), कोटरका के न्यायालय के आदेशों के बाद की गई। पुलिस ने जनता से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने का आग्रह किया है।

सुरक्षा बलों ने हीवान बारामुल्ला में तलाशी अभियान किया शुरू

बारामुला, 27 दिसंबर। सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को बारामुला जिले के हीवान गांव इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर), स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) बारामुल्ला और सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि अभियान के तहत क्षेत्र में सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी का उद्देश्य क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरों को रोकना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

कटरा-रियासी रेलवे ट्रैक पर दौड़ा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इंजन

जम्मू, 27 दिसंबर। उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक परियोजना पर रेलवे द्वारा ट्रायल पर ट्रायल किए जा रहे हैं। दो दिन पहले यहां इस परियोजना के कटरा से रियासी वाले ट्रैक पर सफल इलेक्ट्रिक इंजन ट्रायल किया गया। तो बीते कल 3300 टन वजन की मालगाड़ी को इस ट्रैक पर दौड़ाया गया। लेकिन आज इस ट्रैक पर डबल इंजनों से सफल ट्रायल किया गया है।

श्रीनगर और घाटी के मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, कई सड़के बंद हुईं



श्रीनगर, 27 दिसंबर। श्रीनगर और कश्मीर घाटी के अन्य मैदानी इलाकों में शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे लंबे समय से चल रहा सूखा खत्म हो गया। डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के कुछ हिस्सों से भी बर्फबारी की हुई है, जबकि जम्मू जिले के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। बर्फबारी के कारण दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले को जम्मू जिले के पुंछ और राजौरी जिले

से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड, लद्दाख को जोड़ने वाली श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी रोड के अलावा सिंथन-किश्तवाड़ रोड और कोकरनाग-मारवा-वारवान रोड सहित कुछ रणनीतिक सड़कें भी बंद हो गई हैं।

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में लंबे समय से चल रहे सूखे के बाद मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटक काफी

खुश हुए हैं। पर्यटक डल झील के किनारे फैशनबल बुलेवार्ड रोड पर आलीशान हाउसबोट की पृष्ठभूमि में बर्फ के टुकड़ों का आनंद लेते हुए और जीवन भर के लिए यादगार तस्वीरें विलक करते हुए देखे गए। शुक्रवार को बिजबिहाडा, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और काजीगुंड के कुछ हिस्सों, बारामुला और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों सहित दक्षिण कश्मीर के कई मैदानी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। स्वतंत्र मौसम पूर्वानुमानकर्ता फैजान आरिफ की बताया कि मौजूदा जमीनी अवलोकनों और भविष्य के पूर्वानुमान के आधार पर कुछ ऊंचे इलाकों में महत्वपूर्ण बर्फबारी की उम्मीद है जिसमें 12 से 18 इंच के बीच बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कश्मीर के कुछ मैदानी इलाकों में भी अच्छी बर्फबारी हो सकती है।

वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के विरोध में कटड़ा में तीसरे दिन भी रहा बंद

रियासी, 27 दिसंबर। प्रस्तावित वैष्णो देवी रोपवे परियोजना के विरोध में कटरा में शुक्रवार को तीसरे दिन भी बंद जारी रहा। यहां पहले के प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर और अधिक लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने बुधवार से 72 घंटे के बंद का आह्वान करके घोषणा की थी कि बंद के दौरान जम्मू और कश्मीर के कटरा में सभी गतिविधियां निलंबित रहेगी। बुधवार रात को भूख हड़ताल शुरू करने वाले छह प्रदर्शनकारियों में अब महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो गए हैं। यह सभी लोग विरोध मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए समिति के 18 सदस्यों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति दुकानदारों, टट्टू संचालकों और पालकी मालिकों का प्रतिनिधित्व करती है। समिति का तर्क है कि रोपवे परियोजना

से स्थानीय व्यापार मालिकों की आजीविका नष्ट होगी, इसलिए इस परियोजना को रद्द कर दिया जाए। समिति के आह्वान के बाद शहर भर में काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान दुकानें, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान तीसरे दिन भी बंद रहे और वहांनों की आवाजाही ठा रही। समिति के एक प्रवक्त ने कहा कि यह बंद रोपवे परियोजना के विरोध में हमारे 72 घंटे के बंद का हिस्सा है। यह शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। समिति जल्द ही अगली कार्रवाई के बारे में फैसला करेगी। प्रशासन की भागीदारी की कमी की आलोचना करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि प्रशासन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे महिलाओं और बच्चों सहित लोगों की दुर्दशा के प्रति उदासीन है। भूख हड़ताल में भाग लेने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई होने तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी।

उपायुक्त जम्मू द्वारा कैपेक्स के तहत पीडब्ल्यूडी कार्यों की प्रगति की समीक्षा



जम्मू 27 दिसंबर। उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने जिला कैपेक्स बजट के तहत लोका निर्माण विभाग द्वारा किए गए विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले भर में चल रही परियोजनाओं की स्थिति और वित्तीय प्रगति की

विस्तृत समीक्षा की। समयसीमा का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने निष्पादन एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने पर भी जोर दिया। डीसी ने फंड के उपयोग की स्थिति की भी समीक्षा की और

संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखते हुए फंड का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त शेर सिंह, मुख्य योजना अधिकारी उत्तम कुमार के अलावा पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

डॉ. मनमोहन सिंह के सम्मान में जम्मू-कश्मीर में सात दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा

जम्मू, 27 दिसंबर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सम्मान में 26 दिसंबर, 2024 से 1 जनवरी, 2025 तक सात दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है।

डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हो गया था। इस दौरान सभी आधिकारिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त/सचिव संजीव वर्मा द्वारा सूचित किया गया है कि यह निर्णय दिवंगत नेता के प्रति राध्य के सम्मान को दर्शाता है। नागरिकों से शोक अवधि के दौरान दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है।

अनंतनागा पुलिस ने तीन कुख्यात नशा तस्करों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

27 दिसंबर। ड्रग तस्करों से निपटने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत अनंतनागा पुलिस ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। तीन कुख्यात ड्रग तस्करों पर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है जबकि एक आदतन जालसाज को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है।

जानकारी के अनुसार जुबैर अहमद गनी पुत्र मोहम्मद रसजान गनी

निवासी गुंड बाग सीर हमदान, पुलिस स्टेशन मद्दुन में एनडीपीएस अधिनियम के तहत एफआईआर नंबर 04/2024 में शामिल हैं जहां बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया था। गोपालपोरा मद्दुन निवासी मोहम्मद यूसुफ खान के बेटे बशीर अहमद खान पर पुलिस स्टेशन मद्दुन में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस एफआईआर नंबर 89/2024 में मामला दर्ज है।

तुलखान बिजबेहरा निवासी अब्दुल रशीद भट के बेटे सरतान अहमद भट पर पुलिस स्टेशन बिजबेहरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस एफआईआर नंबर 14/2024 में

मामला दर्ज किया गया है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य ड्रग तस्करी नेटवर्क को बाधित करना और आदतन अपराधियों को उनकी अवैध गतिविधियों को जारी रखने से रोकना है। इसके अतिरिक्त अनंतनागा पुलिस ने पीएसए के तहत एक कुख्यात धोखेबाज बिलाल अहमद लोन उर्फ डॉ. बिलाल' को हिरासत में लिया है जो मरातागाम हंदवाड़ा का निवासी मोहम्मद अकबर लोन का बेटा है। वह कई धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए जाना जाता है और बिलाल अहमद लोन ने काफी सार्वजनिक संकट पैदा किया है।



नए साल को आने में कुछ दिनों का समय बचा है। नए साल पर कई लोग घूमने का प्लान बनाते हैं, तो वहीं कुछ लोग विदेश घूमने का प्लान बनाते हैं। ऐसे में अगर आप भी नए साल पर विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि घूमने के शौकीन लोगों के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, भारत और चीन के नागरिकों को 1 दिसंबर से मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। ऐसे में आप बिना वीजा पर एक पैसा खर्च किए मलेशिया घूमने का प्लान बना सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने अपने एक

भाषण के दौरान यह घोषणा की। इन देशों के नागरिक कर सकेंगे वीजा फ्री यात्रा

मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के अनुसार, चीनी और भारतीय नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक मलेशिया की सैर कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वीजा फ्री एंट्री कब तक लागू रहेगी।

इन देशों में कट सकेंगे वीजा फ्री एंट्री

आपको बता दें कि इस लिस्ट में अब कई देशों का नाम शामिल हो गया है, जहां पर भारतीय नागरिक वीजा

फ्री एंट्री कर सकते हैं। मलेशिया के अलावा भारतीय नागरिक श्रीलंका और थाईलैंड में भी वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं।

भारत और चीन, मलेशिया के चौथे और पांचवें सबसे बड़े सोर्स मार्केट की लिस्ट में शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से जून के बीच मलेशिया में 9.16 मिलियन पर्यटक आए। जिनमें से भारत के 2,83,885 पर्यटक और चीन के 4,98,540 पर्यटक शामिल रहे। वहीं कोरोना महामारी से पहले साल 2019 में भारत से

3,54,486 और चीन से 1,5 मिलियन लोग मलेशिया पहुंचे थे।

वीजा के लिए आवेदन

थाईलैंड ने अपने महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने और सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया। इस साल चीनी और भारतीय नागरिकों को भी यह छूट मिली है। हालांकि वर्तमान समय में भारतीय और चीनी पर्यटकों को मलेशिया जाने के लिए वीजा का आवेदन करना पड़ता है।

मॉरीशस: समुद्र का निराला संसार



दुनिया के बीच डेस्टिनेशन में जिन जगहों को मुख्य रूप से गिना जाता है उनमें मॉरीशस टॉप पर है। हिंद महासागर के नीले गहरे पानी में स्थित मॉरीशस अनूठा है। रंग, संस्कृति और स्वाद में जो विविधता यहां है, वह यहां गुजारे पलों को यादगार बना देती है। इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि लगभग पूरे साल यहां का मौसम लगभग एक सरीखा रहता है। ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ज्यादा ठंड। दिसंबर से मार्च के महीने सबसे ज्यादा बारिश वाले होते हैं, इसलिए उनको छोड़कर बाकी पूरे साल यहां कभी भी जाया जा सकता है। मॉरीशस के सफेद रेतीले तट कोरल रीफ बैरियर से सुरक्षित हैं। यहां का लगभग समूचा तट कोरल रीफ से घिरा है, सिवाय दक्षिणी सिर के कुछ अपवाद को छोड़कर। इसीलिए बाकी तटों पर समुद्र जहां शांत होता है, वहीं दक्षिणी हिस्से में वह बहुत अशांत है। वहां चत्रनी तट पर समुद्र की पछाड़ें देखकर आप मुग्ध हो सकते हैं।

मॉरीशस के मुख्य द्वीप के चारों ओर कई छोटे-छोटे निर्जन द्वीप भी हैं। हम भारतीयों के लिए मॉरीशस उन जगहों में से है, जहां से हमारा भावनात्मक लगाव है। हमारी संस्कृति साझी है और लोग भी। राजधानी पोर्ट लुई पश्चिमी तट पर स्थित है। उत्तर का इलाका मैदानी है और यहां देश के कई सबसे खूबसूरत बीच हैं। समुद्र तटों की रंगीनियत भी सबसे ज्यादा इसी इलाके में है। वहीं पूर्वी मॉरीशस के समुद्र तट सुकून से कुछ पल बिताने के लिए हैं। यहां के समुद्र तट की खूबसूरती खोह और लैगून में है। यहां ब्यू बे और बेले मेरे सबसे लोकप्रिय समुद्री इलाकों में से हैं। उधर पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी तट रोमांच प्रेमियों के लिए स्वर्ग हैं। यहां आप सर्फिंग, स्नोर्कलिंग, डीप शी फिशिंग, जैसे ज्यादातर समुद्री खेल का आनंद आप ले सकते हैं। यहां टेमेरिन बे के आसपास आप डॉल्फिन भी देख सकते हैं। दक्षिणी इलाके का रंगरूप बाकी देश से पूरी तरह अलग है। ग्रेस-ग्रेस ही मॉरीशस के समुद्री तट का अकेला ऐसा इलाका है जहां कोरल रीफ नहीं है। वहां किनारे ऊंची पहाड़ियां और गहरी खाइयां देखने को मिल जाएगी। मॉरीशस का भीतरी इलाका संस्कृति के विभिन्न रंगों से रंगा है। यहां की शिवरात्रि आपको भारत की शिवरात्रि जैसी ही लगेगी।

कैसे जाएं

मॉरीशस के लिए दिल्ली व मुंबई आदि शहरों से कई एयरलाइंस की उड़ानें हैं। दिल्ली से मॉरीशस की सीधी उड़ान लगभग साढ़े सात घंटे का समय लेती है। कई उड़ानें दुबई के रास्ते भी हैं। मॉरीशस का वापसी किराया दिल्ली से 26 हजार रुपये से शुरू हो जाता है। मॉरीशस जाना बेशक महंगा है लेकिन वहां रुकने के लिए लज्जती रिजॉर्ट के अलावा बजट होटल भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे।

इस एक स्थान पर होती है तीन धर्मों की यात्रा



संसार भर में भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग एकजुट होकर रहते हैं। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थल एक ही स्थान पर स्थापित हैं। उन्हीं में से एक तीर्थ है राजगृह। राजगृह हिन्दू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के अनुयायीयों का तीर्थ है। पुरातन काल में राजगृह मागध की राजधानी हुआ करती थी तत्पश्चात मौर्य साम्राज्य आया। महाभारत में राजगृह को तीर्थ माना गया है। राजगृह के समीप अरण्य में जरासंध की बैठक नाम की एक बारादरी अवस्थित है।

हिन्दू तीर्थ

यहां प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी को स्थानीय लोग प्राची सरस्वती कहते हैं। सरस्वतीकुण्ड से आधा मील की दूरी पर सरस्वती को वैतरणी कहा जाता है। इस नदी के तट पर पिण्डदान और गोदान का बहुत महत्व है इसलिए यहां प्रत्येक धर्म-समुदाय के लोग पिण्डदान करते हैं। यहां मार्कण्डेयकुण्ड, व्यासकुण्ड, गंगा-यमुनाकुण्ड, अनन्तकुण्ड, सर्षपिधारा और काशीधारा हैं। जिनके समीप बहुत से देवी-देवताओं के मंदिर अवस्थित हैं।

बौद्ध तीर्थ

पुरातन काल में इस स्थान पर बौद्धों के 18 विहार हुआ करते थे। राजगृह मुख्य बौद्ध तीर्थ है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल का बहुत बड़ा हिस्सा यहां व्यतीत किया था। वर्षा के चार महीने यहीं व्यतीत किया करते थे।

जैन तीर्थ

जैन तीर्थ पंच पहाड़ों पर स्थित है। इक्कीसवें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ का जन्म इसी पहाड़ी पर हुआ था। यही उनकी तपो भूमी थी। मुनिराज धनदत्त और महावीर के बहुत सारे गणधर इसी स्थान से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। जैनयात्री यहां विशेष रूप से दर्शनों के लिए आते हैं।



जर्मनी के प्रचलित शहरों में से एक कोलोन



जर्मनी के प्रमुख शहरों में से एक कोलोन में जमीन पर तो अब रोम साम्राज्य के अधिक अवशेष दिखाई नहीं देते हैं परंतु जमीन के तले आज भी रोम साम्राज्य के प्रभुत्व के प्रमाण मौजूद हैं। एक सीढ़ी की मदद से नीचे उतरने पर रहस्यमयी अंधेरे से घिरे दूसरी सदी की एक कब्रगाह तक पहुंचा जा सकता है। विभिन्न पौराणिक जीवों की आकृतियों से सजा एक विशाल ताबूत यहां दिखाई देता है। इसका ढक्कन हटाया गया है जिसके भीतर झांकने पर सारा डर दूर हो जाता है क्योंकि इसमें कोई भयावह चीज नहीं

बल्कि दो कुर्सियां रखी दिखाई देती हैं। पहली नजर में ये कुर्सियां आजकल की आम कुर्सियां जैसी प्रतीत होती हैं परंतु ध्यान से देखने पर इनका महत्व महसूस होने लगता है क्योंकि इन कुर्सियों को बेहद कलात्मक ढंग से चूना पत्थर से करीब 1800 वर्ष पहले तैयार किया गया था। इन भूमिगत हिस्सों में सब कुछ बेहद प्राचीन है। बेशक कई सौ वर्ष पूर्व कोलोन वासी रोम साम्राज्य से आजाद हो गए थे और जमीन से तो इसके अधिकतर अवशेष हटा दिए गए परंतु जमीन के नीचे आज भी कोलोनिया क्लाऊडिया अरा एग्रीप्पिनेनसियम (वह

उपनिवेश जिससे यह नगर विकसित हुआ) के अवशेष बाकी हैं। गवर्नर के महल प्रायटोरियम का पता ही नहीं चलता यदि द्वितीय विश्व युद्ध में कोलोन शहर का मध्य हिस्सा नबाह न हुआ होता। आज पर्यटक इस महल के अवशेषों की सैर कर सकते हैं जो सोमवार को छोड़ कर सप्ताह के बाकी दिन खुला रहता है इसके ठीक साथ प्राचीन गटर है। रोमन 100 किलोमीटर दूर एफिल पहाड़ियों से ताजा पानी कोलोन तक लाए थे जबकि गंदे पानी की निकासी वे राइन नदी में करते थे। इसके लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल प्राचीन रोमन करते थे उसका पता अन्वों को 19वीं सदी में जाकर लगा था। इस जर्मन शहर में रोम साम्राज्य के कई नए अवशेषों का भी पता चलता रहा है, विशेषकर भूमिगत रेलवे के लिए की जाने वाली खुदाई के चलते कई अवशेषों का पता चल रहा है। हालांकि शहर के भीतरी हिस्से में रहने वाले किसी भी इंसान को प्राचीन अवशेषों का पता चल सकता है। 1965 में एक व्यक्ति को अपने घर के बेसमेंट की खुदाई में कुछ पत्थरों से बने हिस्से मिले थे जो एक प्राचीन स्मारक निकला। आज यह रोमन-जर्मनिक म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। इससे पहले 1941 में भी एक बंकर की खुदाई के दौरान एक खोज हुई थी। तब भगवान डाइओनीसोस का एक मोजायक मिला था जिसमें 15 लाख टाइल्स लगी थीं। यदि आप जानना चाहें कि प्राचीन रोम वासी किस तरह से स्पा का आनंद लिया करते थे तो आपको कोलोन से निकल कर करीब स्थित जुएलपिच कस्बे तक जाना होगा। वहां म्यूजियम ऑफ बैथ कल्चर में प्राचीन रोम के स्नानागारों के संरक्षित अवशेष सहेज कर रखे गए हैं। संग्रहालय में मॉडल्स बना कर रोम कालीन स्नानागारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गहरे रंग में रंगे स्नानागारों में कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम बने हैं। स्वीटिंग या हॉट बैथ में स्नान करने से पहले शरीर पर तेल लगाया जाता था या मालिश करवाई जाती थी। फिर करीब 40 डिग्री तक गर्म पानी में स्नान किया जाता था। बाद में वे ठंडे पानी में नहाते थे। स्नानागारों में केश विन्यासक, चिकित्सक तथा रसोइए भी मेहमानों की सेवा में मुस्तैद रहते थे। स्नानागारों के नीचे गुलाम लगातार आग जला कर रखते थे जिसकी ऊष्मा फर्श तथा दीवारों बने छिद्रों से होकर स्नानागार तक पहुंचती रहती थी। जब आग के लिए लकड़ी पाने के लिए आस-पास के जंगलों के पेड़ों को काट कर खत्म कर दिया गया तो प्राचीन रोम वासी ब्लैक फॉरेस्ट से लकड़ी काट कर राइन नदी के रास्ते कोलोन तक पहुंचाने लगे थे। उस वक्त अभिजात्य वर्ग के रोम वासियों के लिए विशेष शौचालय भी बनाए गए थे जहां वे एक साथ बैठ कर निवृत्त होते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श भी किया करते थे। इतिहास पर नजर डालें तो कोलोन की खूबियों ने रोमन साम्राज्य का मन पूरी तरह मोह लिया था। इतिहास बताता है कि हर किसी ने कोलोन को अपना बनाने की कई कोशिशें कीं। यह रोमन साम्राज्य का एक बड़ा केंद्र रहा। 12 हजार साल पहले राइन नदी के किनारे रोमन साम्राज्य का विस्तार केंद्र कोलोन ही था। रोम शासकों ने यहां अपनी व्यापारिक चेकी स्थापित की थी और नाम दिया था कोलोनिया। रोमन दौर की निशानियां कोलोन में आज भी यहां वहां बिखरी हुई हैं। राइन नदी इलाके में व्यापार का प्रमुख रास्ता रहा है और इसकी बदौलत कोलोन की समृद्धि भी रही। मध्ययुगीन दौर में रोमन शासन के बनाए 12 चर्च और किले सरीखे तीन नगर द्वार कोलोन की विशिष्टता रहे हैं।



अरुणा जसरोटिया ने सुनीं जन शिकायतें, समाधान का दिया आश्वासन



कटुआ 27 दिसंबर (हि.स.)। जसरोटा विधायक राजीव जसरोटिया की पत्नी अरुणा जसरोटिया ने शुक्रवार को जन शिकायतें सुनने के लिए सुफेन, गमेला, जगेडा गांवों का दौरा किया। बैठकों में दुकानदारों, गणमान्य नागरिकों और युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई।

इस अवसर पर बोलते हुए अरुणा ने कहा कि भाजपा स्थानीय लोगों को अपनी शिकायतें कहने और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक खुला मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न व्यक्तिगत मुद्दों के अलावा, पीपचर्ड, पीडीडी, सड़कों, गलियों, नालियों आदि से संबंधित अन्य मुख्य मुद्दे प्रस्तुत किए गए, सभी मुद्दों के

लिए अरुणा ने सभा को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा। अरुणा ने शिकायतों को सुनते हुए कहा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए हम संबंधित अधिकारियों से ज़रूरतमंद व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक एक जवाबदेह राजनीतिक पार्टी के समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं तक पहुंचने और उन्हें हल करने में भाजपा की प्रतिबद्धता पर

भरोसा करते हुए लोग पार्टी कार्यालय में अपनी समस्याएं रखने के लिए आते हैं और पार्टी पर दृढ़ विश्वास रखते हैं।

अरुणा ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोषित मिशन सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि जाति, धर्म और क्षेत्र से परे समाज के सभी वर्गों को प्रगति और विकास के पथ पर सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने आम जनता को सुशासन प्रदान करने के भाजपा के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों की पीड़ा को दम करने के लिए प्रतिबद्ध है और वर्ष के 365 दिन जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा जम्मू-कश्मीर में सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन भाजपा के सभी विधायक जनता की पीड़ा को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उपायुक्त जम्मू द्वारा कैपेक्स के तहत पीडब्ल्यूडी कार्यों की प्रगति की समीक्षा

जम्मू 27 दिसंबर। उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने जिला कैपेक्स बजट के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले भर में चल रही परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। समयसीमा का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने निष्पादन एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखने पर भी जोर दिया। डीसी ने फंड के उपयोग की स्थिति की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखते हुए फंड का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त शेर सिंह, मुख्य योजना अधिकारी उत्तम कुमार के अलावा पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, उप-मंडल मजिस्ट्रेट और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

डॉ. जसरोटिया ने वीर बल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों के सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डाला

जम्मू, 27 दिसंबर, हि.स.। वीर बल दिवस के समापन पर भाजपा पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता डॉ. अभिजीत जसरोटिया ने धर्म के नाम पर गुरु गोबिंद सिंह जी के चार बेटों साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान पर जोर दिया।

राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस सप्ताह में बाबा फतेह सिंह जी उम्र 6 वर्ष और बाबा जोरावर सिंह जी उम्र 9 वर्ष की असाधारण वीरता को श्रद्धांजलि दी गई जिन्हें मुगल शासक औरंगजेब के अधीन जबरन धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर सरहिंद में जिंदा ईदों से चिन्वा दिया गया था।

डॉ. जसरोटिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुरु गोबिंद सिंह जी का बलिदान जिन्होंने मानवता और

राजौरी के सुदूर गांव में मोबाइल मेडिकल गश्ती का आयोजन किया



जम्मू, 27 दिसंबर (हि.स.)। राजौरी में मोबाइल मेडिकल गश्ती के साथ सुदूर गांव सिचका में पहुंचकर भारतीय सेना ने गुजरन और बक्ररवाल समुदायों सहित स्थानीय ग्रामीणों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कीं। चुनौतीपूर्ण भूभाग और मुख्यधारा की स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुंच के कारण ये समुदाय अक्सर स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण असमानताओं का सामना करते हैं।

भारतीय सेना की पहल का उद्देश्य इस अंतर को पाटना है जिससे उनके दरवाजे पर सीधे बहुत जरूरी चिकित्सा सुविधा

प्रदान की जा सके।

आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति से लैस मोबाइल मेडिकल गश्ती ने बुनियादी स्वास्थ्य आकलन, दवाओं का वितरण, निवारक देखभाल, टीकाकरण, और स्वच्छता, पोषण और बीमारी की रोकथाम पर शिक्षा फैलाई। महिलाओं के स्वास्थ्य पर मुख्य ध्यान दिया गया। कुल 37 व्यक्तियों (22 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे) को प्रदान की गई चिकित्सा सेवाओं से लाभ मिला। स्थानीय लोगों ने सेना द्वारा प्रदान की गई दयालु देखभाल और सहायता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।

उपायुक्त उधमपुर द्वारा पीएमएवाई-शहरी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा



उधमपुर 27 दिसंबर। प्रधानमंत्री

आवास योजना-शहरी योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए डीसी कार्यालय परिसर के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में उपायुक्त उधमपुर सलोनी राय की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। बैठक में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त राजेंद्र सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त प्रेम सिंह, नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजिंदर डिग्रा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी

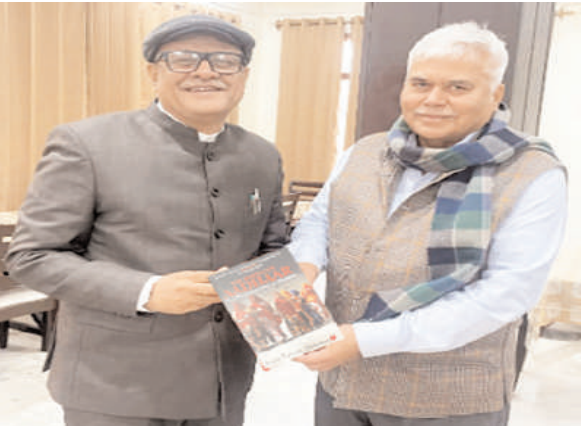
शामिल हुए।

उपायुक्त ने पीएमएवाई-यू योजना के तहत शहरवार पंजीकरण की स्थिति का आकलन किया और संबंधित अधिकारियों को जिले की तीनों नगर पालिकाओं में विशेष शिबिर आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्तियों की एक व्यापक सूची तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में

डॉ. राम सेवक शर्मा ने एसएमवीडीयू के कुलपति प्रो. प्रगति कुमार को आधार का निर्माण भेंट किया

जम्मू, 27 दिसंबर (हि.स.)। प्रख्यात नौकरशाह और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राम सेवक शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय (एसएमवीडीयू) का दौरा किया और अपनी पुस्तक, द मैकिंग ऑफ़ आधार- वल्ड्स लार्जैस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, एसएमवीडीयू के कुलपति प्रो. प्रगति कुमार को भेंट की।

यह पुस्तक दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली आधार के निर्माण का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है जिसने 1.3 बिलियन से अधिक भारतीयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। डॉ. शर्मा ने आधार के विकास के दौरान सामने आई तकनीकी, प्रशासनिक और नीतिगत चुनौतियों पर प्रकाश डाला जिसमें दिखाया गया कि कैसे इस परियोजना ने पहचान सत्यापन में क्रांति ला दी और भारत में



डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दिया। पुस्तक प्राप्त करते समय प्रो. प्रगति कुमार ने डॉ. शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और आधार की अभूतपूर्व सफलता की सराहना की। उन्होंने कहा आधार न केवल एक तकनीकी मील का पथर है बल्कि भारत की अभिनव भावना का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह पुस्तक शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और प्रौद्योगिकीविदों को प्रेरित करेगी जो

जेडीए को सिदड़ा में वाटर पार्क बनाने का जिम्मा सौंपा गया

जम्मू 27 दिसंबर। मुख्य सचिव अटल डूडू ने सिदड़ा, जम्मू में तवी नदी के किनारे वाटर थीम पार्क स्थापित करने के विभिन्न तरीकों और साधनों की उपयुक्तता पर चर्चा करने हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आयुक्त सचिव आवास एवं शहरी विकास विभाग, आयुक्त सचिव पर्यटन, वीसी जेडीए तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने तवी नदी के किनारे सिदड़ा गोल्फ कोर्स के आसपास विभाग द्वारा पहचानी गई भूमि की स्थिति पर ध्यान दिया। उन्होंने आवास विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भूमि, खासकर वन विभाग से एनओसी लेने के लिए सभी तरह के अवरोधों से मुक्त हो। उन्होंने जम्मू विकास प्राधिकरण को सलाह दी कि वे इस बेशकीमती जमीन का इस्तेमाल परियोजना में अपनी इकटिरी के तौर पर करें, ताकि यह प्राधिकरण के लिए नियमित आय का स्रोत बन सके। उन्होंने उन्हें तैयार योजना के अनुसार पीपीपी मॉड में इस साइट पर एक थीम आधारित जल मनोरंजन पार्क बनाने के लिए

ईओआई आमंत्रित करने को कहा।

अटल डूडू ने इस मामले को जेडीए के संबंधित निदेशक मंडल के समक्ष ले जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने का अधिकार उसी को हो। उन्होंने कहा कि यह पार्क जम्मू में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने के साथ-साथ तवी लेक प्रैट, जूलॉजिकल पार्क और यहां बनाई गई अन्य सुविधाओं में एक नया स्थान होगा। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ इस तरह के मनोरंजन से यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और जम्मू अपने आप में एक पर्यटन स्थल बन जाएगा। आयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी विकास विभाग मनदीप कौर ने बैठक में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस वाटर पार्क के विकास के लिए जेडीए द्वारा तवी नदी के किनारे गांव द्वार (सिधरा क्षेत्र, गोल्फकोर्स से सटा हुआ) में 92 कनाल और 3 मरला भूमि की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 0.4 किलोमीटर दूर है और इस परियोजना के लिए उपयुक्त है।

जावेद डार ने डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया

जम्मू 27 दिसंबर। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में मंत्री ने डॉ. मनमोहन सिंह को एक अनुकरणीय नेता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और दूरदर्शी राजनेता बताया, जिनके योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में डॉ. सिंह के कार्यकाल और उनके क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों ने भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति का मार्ग प्रशस्त किया। मंत्री ने कहा, डॉ. मनमोहन सिंह ने केवल एक सम्मानित नेता थे, बल्कि वे उन असंख्य व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शक भी थे, जो ईमानदारी और समर्पण के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं।

पुलिस की साइबर यूनिट ने 2,16,400 रुपये की ऑनलाइन ठगी की रकम बरामद

डोडा, 27 दिसंबर हि.स.। जम्मू-कश्मीर पुलिस जिला डोडा द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस जिला डोडा की सीसीआईयू साइबर अपराध जांच इकाई ने साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में उच्चतम स्तर की व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है जिसमें 2,16,400 रुपये की ऑनलाइन ठगी की रकम को सफलतापूर्वक सुलझाया और बरामद किया गया।

डोडा पुलिस ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि युनिट को शिकायतकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुईं जिसमें फोजिया बानो पुत्री मोहम्मद रफी निवासी खेलनी डोडा, जहौर अब्बास पुत्र अब्दुल रशीद वानी निवासी जटी अस्सरा, शफीका बेगम पत्नी तालिब हुसैन निवासी काको

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कटरा रोपवे परियोजना पर चिंता जताई, तत्काल रोक लगाने की मांग

जम्मू, 27 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने श्री माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल के लिए प्रस्तावित रोपवे परियोजना का कड़ा विरोध किया है, उन्होंने कटरा शहर की धार्मिक परंपराओं, आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव का हवाला दिया है।

आज जारी एक बयान में, गुप्ता ने कटरा में चल रहे आंदोलन के कारण होने वाले व्यवधान को उजागर किया, जहां शहर लगातार तीन दिनों से बंद है। उन्होंने तीर्थयात्रा के अनुभव और श्राइन बोर्ड की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि देश भर और विदेश से हजारों भक्तों को विरोध के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गुप्ता ने चेतावनी दी कि रोपवे परियोजना बाण गंगा, चरण पादुका, अर्ध कुंवारी और हाथी मठ जैसे प्रमुख पवित्र स्थलों को



दरकिनार करके तीर्थयात्रा की पवित्रता से समझौता कर सकती है। उन्होंने कहा, ये स्थल आध्यात्मिक यात्रा के अभिन्न अंग हैं और इनका गहरा धार्मिक महत्व है। पारंपरिक मार्ग में बदलाव से तीर्थयात्रा की पवित्रता कम हो जाएगी, जो सदियों से अपरिवर्तित रही है। वरिष्ठ एनसी नेता ने कटरा के निवासियों के लिए आर्थिक निहितार्थों पर जोर देते हुए कहा कि 50,000 से अधिक लोग – जिनमें व्यापारी, पिट्ट, टट्टू वाले, पालकी वाले और दुकानदार शामिल हैं – अपनी आजीविका के लिए तीर्थयात्रा पर निर्भर हैं।

—

+

+

+

+

कंडी क्षेत्रों में बंदरों का कहर, हजारों एकड़ भूमि हो रही बंजर

कटुआ 27 दिसंबर (हि.स.)। जिला कटुआ के ब्लॉक बरनोटी के पंचायत बरवाल सहित अन्य कंडी क्षेत्रों में बंदरों का कहर जारी है। गांव वासी पिछले दो वर्षों से नहीं लगा पा रहे कोई भी फसल, क्योंकि बंदर उन फसलों को खराब कर रहे हैं। जिसकी वजह से कंडी क्षेत्र में ज्यादातर भूमि बंजर हो रही है। जिला कटुआ की पंचायत बरवाल में बंदरों का कहर जारी है पिछले तीन वर्ष से गांव वासी अपने खेतों में किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर रहे हैं। दरअसल बंदर उन खेतों में हुड़दंग मचा कर फसलों को खराब कर रहे हैं जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने अपने खेतों में खेती करना छोड़ दी है। जिस वजह से कंडी क्षेत्र में ज्यादातर जमीनें बंजर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बंदरों के आतंक से उन्हें निजात दिलवाई जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे नहीं जानते कि बंदर कंडी क्षेत्र में कहां से आए, उनका कहना था कि आज से पांच वर्ष पहले कंडी क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में मात्र चंद्र बंदर ही जगलों में घूमते थे, लेकिन अब बंदर बरित्यों तक पहुंच चुके हैं जो रोजाना लोगों की छतों पर हुड़दंग मचाते हैं और भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

उपायुक्त ने वन मंजूरी और अभिसारी विकास परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया



राजौरी 27 दिसंबर। उपायुक्त राजौरी अभिषेक शर्मा ने अपने कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वन विभाग द्वारा कैप्पा और कैपेक्स योजनाओं के तहत चल रही परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में वन मंजूरी के मुद्दों के समाधान का भी आकलन किया गया, जो जिले में विकास परियोजनाओं में बाधा बन रहे हैं।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने परियोजनाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले भूमि संबंधी मुद्दों के शीघ्र निपटान के महत्व पर बल दिया।

उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त राजस्व राजौरी को स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं और डीडीसी कार्यालय परिसर सहित विकास परियोजनाओं की शुरुआत को

प्रभावित करने वाली सभी भूमि संबंधी चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने का निर्देश दिया।

संसाधनों के प्रभावी अभिसरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उपायुक्त ने प्रभागीय वन अधिकारी, मृदा संरक्षण को मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग और जिला खनिज फ़ंडेशन पहल के तहत खनन विभाग के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय के तकनीकी विशेषज्ञों सहित इंजीनियरिंग विंग से विशेषज्ञता का उपयोग करने और परियोजनाओं की बेहतर योजना और निष्पादन के लिए समोच्च मानचित्रण तकनीकों को शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया।

उपायुक्त ने वन, जनजातीय मामले और पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी हितधारकों के विकासात्मक पहलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने और जमीन पर ठोस परिणाम प्राप्त करने का आग्रह किया।

बैठक में एडीडीसी राजौरी डॉ. राज कुमार थापा, एसई पीडब्ल्यूडी, राजौरी और नौशेरा के डीएफओ, डीएफओ मृदा संरक्षण, सीएमओ राजौरी, वन संरक्षण विभाग के सहायक निदेशक और अन्य जिला और क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित थे।



जम्मू, 27 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूजे) ने कैपेस प्लेसमेंट को लेकर एक और उपलब्धि हासिल की। 2025 की कक्षा के 50 से अधिक छात्रों ने प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट हासिल किया यही। इस वर्ष प्रमुख भर्तीकर्ताओं में प्लैनेट स्पार्क, स्क्रिप्ट स्पेस, बेस्टसेलर, एचडीएफसी लाइफ़, ईज माई ट्रिप, ट्रैवल लैंड, ट्रूविया ग्लोबल, होमिन्स एंजिनीयर्स, सिंथिड लैब्स, फ़िलपकार्ट, टीसीएस और गोदरेज शामिल थे। एमबीए-एचआर, गणित, अर्थशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, बी.वोकल, जूलॉजी और पर्यावरण विज्ञान जैसे

विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्रों ने प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लिया। प्लेसमेंट सीजन में 6.6 एलपीए का उच्चतम पैकेज दर्ज किया गया है जबकि औसत पैकेज 3.63 एलपीए रहा। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट कार्यालय द्वारा आयोजित प्लेसमेंट अभियान का उद्देश्य छात्रों को बीमा, बैंकिंग, बिज्नी, पर्यटन, अनुसंधान और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में अवसरों से लैस करना था। भर्तीकर्ताओं ने विभिन्न भर्ती मापदंडों पर छात्रों का मूल्यांकन किया, उन्हें न केवल नौकरी के प्रस्ताव दिए बल्कि उद्योग के बारे में मूल्यवान जानकारी भी दी।

—

+

+

—

+

संपादकीय

जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाएँ

इसमें कोई संदेह नहीं है कि चल रही प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना भारत सरकार का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बनने जा रही है क्योंकि इस योजना के तहत लाभ पूरे देश में फैलना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के मामले में, जो अपने निवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी उपलब्ध कराने में आत्मनिर्भर है, यह ज़रूरी है कि प्रकृति के इस गुण का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए और उन संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए जाएँ जो मनुष्यों के साथ-साथ यूटी के वनस्पतियों और जीवों की सबसे जरूरी ज़रूरतों में से एक को पूरा करते हैं, ताकि इसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। बर्बादी को रोकने के अलावा, जल स्रोतों को रिचार्ज करने की एक और बात की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले समय में भी जम्मू-कश्मीर में पानी प्रचुर मात्रा में बना रहे और अगली पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।

इस संबंध में विधायक शाम लाल शर्मा द्वारा दिया गया सुझाव अमूल्य है, क्योंकि उन्होंने लोगों से क्षेत्र में घटते जल स्तर को पुनर्जीवित करने के लिए वर्षा जल संचयन अपनाने को कहा है।

यह उल्लेख करना उचित है कि वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को बाद में उपयोग के लिए एकत्रित करने और संग्रहीत करने की प्रक्रिया है। यह आमतौर पर छतों से वर्षा जल को इकट्ठा करके, इसे टैंकों या भूमिगत जलाशयों में संग्रहीत करके और इसे सिंचाई, पीने और घरेलू जरूरतों जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए फ़िल्टर करके किया जाता है। यह पानी के संरक्षण में मदद करता है, नगरपालिका आपूर्ति पर निर्भरता को कम करता है और पानी की कमी को दूर कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ ताजे पानी की कमी है। इसके अलावा, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इसका उपयोग जल स्तर को फिर से जीवंत करने के लिए इष्टतम रूप से किया जा सकता है, जो इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अत्यधिक उपयोग के कारण सतह के नीचे का पानी बहुत तेजी से कम हो रहा है। क्षेत्र के लोगों को ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों से सीख लेनी चाहिए, जहाँ ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जो लोगों और यहाँ तक कि जानवरों और पौधों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से वर्षा जल संचयन पर निर्भर हैं। जम्मू-कश्मीर में भी इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बारिश तो निश्चित रूप से आएगी और बिना किसी भेदभाव के क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराएगी।

कुल मिलाकर, भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है और इसके लिए लोगों को धन की आवश्यकता है। भारत सरकार और इस मामले में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जम्मू-कश्मीर सरकार भी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुपत बिजली योजना जैसी योजना की परिकल्पना कर सकती है, जिसमें वर्षा जल संचयन को सब्सिडी देकर इसे घरेलू मामला बनाया जा सके, क्योंकि यह लोगों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के मामले में बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

यह आवश्यक है कि संबंधित अधिकारी इस पर विचार करने में अधिक समय बर्बाद न करें और इस योजना को लेकर आगे आएँ, क्योंकि यह भी लाभों से भरपूर होगी और इसमें कोई कमी नहीं होगी।

डॉ. मनमोहन सिंह : आधुनिक भारत के आर्थिक बदलाव के सूत्रधार

– योगेश कुमार गोयल

देश के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के साथ ही एक ऐसे नेता के युग का अंत हो गया, जिसने आधुनिक भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मनमोहन सिंह ने 92 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली।

अपने शांत स्वभाव और बौद्धिक कौशल के लिए जाने जाने वाले मनमोहन सिंह ने भारत में ऐतिहासिक आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाई थी। 1991 में व्यापक सुधारों का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को खोला, तथाकथित लाइसेंस-परमिट राज को खत्म किया और वैश्विक मंच पर भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनने के मार्ग पर मजबूती से स्थापित किया। एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी यात्रा न केवल प्रेरणादायक रही बल्कि उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और राजनीतिक निर्णयों ने भारत के इतिहास में एक नई दिशा दी। उन्हें आधुनिक भारत के आर्थिक सुधारों का वास्तुकार भी कहा जाता है।

डॉ. मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में अपने बजट भाषण के अंत में फासिसी लेखक विक्टर ह्यूगो की पंक्तियां उद्धृत करते हुए कहा था- दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती, जिसका समय आ गया है। में इस सम्मानित सदन को सुझाव देता हूं कि भारत का दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उदय एक ऐसा विचार है, जिसका समय अब आ चुका है।

मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने आर्थिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि की। 2004 से 2014 तक भारत 10वें स्थान से उठकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, जिससे लाखों लोगों का जीवन स्तर सुधरा और गरीबी में कमी आई थी। मनमोहन सिंह ने एक दशक से भी ज्यादा समय तक अभूतपूर्व विकास और वृद्धि की दिशा में देश को नेतृत्व प्रदान किया। उनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में उदारीकरण के तहत लाइसेंस राज की समाप्ति और व्यवसाय शुरू करने के लिए सरल प्रक्रियाओं का निर्माण, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के दरवाजे खोलना और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बाजार पर आधारित सुधार लागू करना, ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए ‘मनरेगा’ लागू करना शामिल हैं। इन सुधारों ने



भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और उसे विश्व अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया।

भारत ने डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक वृद्धि दर देखी, जो औसतन 7.7 प्रतिशत रही और उसी के परिणामस्वरूप भारत करीब दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में सफल रहा था। उन्हें न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विमग्न, मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें न केवल उन कार्यों के लिए स्मरण किया जाता रहेगा, जिनके जरिये उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा। उन्होंने न केवल आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा बल्कि सामाजिक और विकासशील नीतियों पर भी जोर दिया। हालांकि उनका कार्यकाल आलोचनाओं से भी अछूता नहीं रहा। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें आर्थिक चुनौतियों और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा और निर्णय लेने में धीमापन उनकी सरकार के लिए नकारात्मक साबित हुए। 21 घोटाला उनके कार्यकाल के सबसे बड़े विवादों में से एक रहा। इसके अलावा कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले को ‘कोलगेट’ के नाम से जाना गया। उनके दूसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों की गति धीमी रही।22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक दो बार भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह की छवि बेहद कम बोलने वाले और शांत रहने वाले व्यक्ति की रही। हालांकि जब भी वे कुछ बोलते थे, वह सुर्खियां बन जाती थीं। मनमोहन सिंह ने ही कहा था कि राजनीति में लंबे समय तक कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वह कहा करते थे कि मैं एक खुली किताब की तरह हूं और मेरे दुश्मन वष का कार्यकाल इतिहासकारों के मूल्यांकन का विषय है। उन्होंने 27 अगस्त 2012 को संसद में कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है, जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। डॉ. मनमोहन सिंह को उनके अलोचकों द्वारा ‘मूक प्रधानमंत्री’

की संज्ञा दी जाती थी लेकिन उन्होंने आमतौर पर इस पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर उनकी पहली प्रतिक्रिया दिसंबर 2018 में उनकी पुस्तक ‘द चेजिंग इंडिया’ के विमोचन के अवसर पर सामने आई थी, जब उन्होंने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि मैं एक मूक प्रधानमंत्री था, मुझे लगता है कि मेरी ये पुस्तकें बोलती हैं।

बतौर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह लोकसभा में 23 मार्च 2011 को विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। उस दौरान सदन में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने उन पर तंज करते हुए कहा था, ‘तू झंघर-उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहवरी का सवाल है।’ इसके जवाब में डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था, ‘माना के तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शोक तो देख मेरा इंतजार तो देख।’ डॉ. मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में बतौर प्रधानमंत्री अपनी आखिरी प्रेस कांफेंस में मीडिया के उन सवालों का जवाब देते हुए, जिनमें कहा गया था कि उनका नेतृत्व कमजोर है और कई अवसरों पर वे निर्णायक नहीं रहे, कहा था कि मैं यह नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूं बल्कि मैं ईमानदारी से यह मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्ष की तुलना में ज्यादा उदार होगा, राजनीतिक मजबूरियों के बीच मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। उन्होंने कहा था कि परिस्थितियों के अनुसार मैं जितना कर सकता था, उतना किया। यह इतिहास को तय करना है कि मैंने क्या किया है या क्या नहीं किया है। उनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि मीडिया की तुलना में इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा।

26 सितंबर 1932 को पंजाब (अब पाकिस्तान में) के गांव गाह में जन्मे मनमोहन सिंह का परिवार विभाजन के समय भारत आ गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में हुई थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डिप्लोमा किया और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। उनकी उच्च शिक्षा ने उन्हें न केवल

भारत ने डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक वृद्धि दर देखी, जो औसतन 7.7 प्रतिशत रही और उसी के परिणामस्वरूप भारत करीब दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में सफल रहा था। उन्हें न केवल उनके विजन के लिए जाना जाता है, जिसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाया बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके विमग्न, मृदुभाषी व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें न केवल उन कार्यों के लिए स्मरण किया जाता रहेगा, जिनके जरिये उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया बल्कि एक विचारशील और ईमानदार व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाएगा।

उन्होंने न केवल आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा बल्कि सामाजिक और विकासशील नीतियों पर भी जोर दिया। हालांकि उनका कार्यकाल आलोचनाओं से भी अछूता नहीं रहा। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें आर्थिक चुनौतियों और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा और निर्णय लेने में धीमापन उनकी सरकार के लिए नकारात्मक साबित हुए।

एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री बनाया बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य और आर्थिक सोच की गहराई भी प्रदान की। अपने कैरियर की शुरुआत उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से की और बाद में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारतीय रिजर्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी कार्य किया।वे 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और उस दौरान उन्होंने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने तथा मुद्रा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत के आर्थिक इतिहास में

1991 का वर्ष एक निर्णायक मोड़ था क्योंकि उस समय देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डा. मनमोहन सिंह को वित्तमंत्री नियुक्त किया। वित्तमंत्री के रूप में उन्होंने सार्हसिक आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया, जिनमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रमुख थे। बहरहाल, राजनीति में डा. मनमोहन सिंह जैसे विद्वान बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उनकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के

बावजूद उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी हमेशा संदेह से परे रही। वह एक ऐसा राजनेता थे, जिन्हें राजनीतिक सीमाओं से परे सम्मान प्राप्त था। कुल मिलाकर, तमाम आलोचनाओं के बावजूद डा. मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाएंगे, जिन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर सम्मानजनक स्थान दिलाया और भारत को आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अहम योगदान दिया।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

स्मृति शेष : डॉ. मनमोहन सिंह

डॉ. रमेश ठाकुर
बानवें वर्ष की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत ने अर्थव्यवस्था की विप्लवग्न वास्तुकार खो दिया। पूरे संसार की आंखें उनके निधन से नम हैं। दो बार प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने 5 ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिन्हें मौजूदा क्या, आने वाली पीढ़ियां स्मरण करती रहेंगी। 2005 में ‘सूचना का अधिकार’ और उसी साल ‘मनरेगा कानून’ लागू किया जाना, इनमें शामिल है। फिर साल 2009 में ‘शिक्षा का अधिकार कानून।’ वहीं, 2013 में दो बड़े फैसले ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून’ और ‘भूमि अधिग्रहण कानून’ पर फैसले को हर भारतीय याद करेगा।

डॉ. सिंह को अर्थव्यवस्था का सूत्रधार कहा गया। देश की नाजुक अर्थव्यवस्था के दौर में बने वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के दो साल के कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था में सुधार के उनके फैसलों के सभी कायल हैं। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई तो प्रणब मुखर्जी का नाम सबसे आगे था लेकिन प्रणब मुखर्जी ने खुद आगे बढ़कर सोनिया गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से गुहार लगाई कि देश की अर्थव्यवस्था जिण रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें डॉ. मनमोहन सिंह से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। साल 1991 में वित्तमंत्री रहते उन्होंने जब देश की नाजुक अर्थव्यवस्था को संभाला था, तब स्वयं अटल बिहारी वाजपेई ने उनकी तारीफ की। उनके वित्तमंत्री रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव ने उन्हें अहम फैसलों के लिए पूरी ताकत दी। यह ऐसा दौर था जब वित्तमंत्री के तौर पर डॉ. मनमोहन सिंह ने दशकों से बंद पड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवारों को खोलने की शुरुआत की। वित्तमंत्री रहते लाइसेंस राज को खत्म करने का श्रेय उन्हें जाता है। उन्होंने सबसे पहले विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का काम किया और भारत के भीतर विदेशी कारोबार के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया कराया। भारत में बाहरी कंपनियों के आगमन की शुरुआत यहीं से हुई। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था के अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधारक माना गया है। एकबार खुद उन्होंने स्वीकारा था कि विश्व के उच्च शिक्षा संस्थान में पढ़ने के बाद ही उन्हें देश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां को सभालने का अवसर मिला। इसलिए वह उच्च शिक्षा के सदैव पक्षधर रहे। प्रत्येक निर्णय में उनका धैर्य, संयम, निस्पृहता और उदारता देखने लायक होती थी। दबाव में आकर या जल्दीबाजी में उन्होंने कभी कोई निर्णय नहीं लिया। 2005 में मनरेगा का जब फाइनल ड्राफ्ट उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने उसमें फेरबदल को कहा। इसे लेकर सोनिया गांधी की नाराजगी भी सही लेकिन बाद में हुआ वही जो मनमोहन सिंह चाहते थे।

मनमोहन सिंह का व्यक्तिव निःसंदेह करिश्माई था। अस्सी के दशक में जिन्होंने भी विभिन्न भारतीय नोटों में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उनका नाम और हस्ताक्षर देखें होंगे, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री का ओहदा भी संभालेगा। एक बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। उसके बाद वह बिना कोई चुनाव लड़े देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। डॉ. मनमोहन सिंह रिकॉर्ड 33 वर्ष तक राज्यसभा में सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे। वर्ष-1991 में वह पहली बार राज्यसभा पहुंचे। उसके 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर से राज्यसभा के लिए चुने गए। सन 1998 से लेकर 2004 के बीच वह राज्यसभा में नेता विपक्ष का ओहदा भी संभाला।

इसके अलावा वह वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, यूजीसी अध्यक्ष और आरबीआई गवर्नर भी रहे। कुल मिलाकर उन्होंने देश के बड़े पदों पर रहते इस पद को सार्थक बनाया। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के तीनों संस्करणों में उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

करोड़ों रुपये पर प्रकाश डाला, जो सरकार के कुल कर राजस्व का 0.1% से भी कम था। जेटली ने तर्क दिया कि उच्च प्रशासनिक लागत और कम उपज वाले करों को अधिक कुशल विकल्पों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्राचीन मिस्र का पपीरस एक व्यक्ति की कहानी बताता है जो अपनी संपत्ति का कम मूल्यांकन करके विरासत करों से बचने का प्रयास चले गए। इस तरह की चोरी की सजा-कोड़े मारना। आधुनिक, वैश्वीकृत दुनिया में, पूंजी की गतिशीलता जटिलता की एक और प्रतीक बन गई है। उच्च करों के कारण पूंजी पलायन हो सकता है, जहां धनी व्यक्ति दुबई जैसे कर-अनुकूल क्षेत्राधिकारों में बसने के लिए देश छोड़ देते हैं। यह नौवें जैसे देशों में देखा गया है, जहाँ संपत्ति करों में वृद्धि के कारण कई उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्ति विदेश चले गए। भारत में विदेश में स्थानांतरित होने वाले करोड़पतियों की संख्या में

भी वृद्धि देखी गई है। 2023 में, लगभग 5, 100 भारतीय करोड़पति वित्तीय और कर-सम्बंधी कारणों का हवाला देते हुए विदेश चले गए। भारत में संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भूमि, अचल संपत्ति और सोने से जुड़ा हुआ है। इन परिसंपत्तियों को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिससे सवाल उठता है कि व्यवहार में संपत्ति कर कैसे लागू किया जाएगा। यह देखते हुए कि भारत में संपत्ति सर्जन अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, ऐसे कर लगाने से आर्थिक प्रगति में बाधा आ सकती है। यह व्यक्तियों के लिए अधिक कमाने और निवेश करने की प्रेरणा को कम कर सकता है, जिससे देश की वृद्धि धीमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यह निजी संपत्ति सर्जन और उद्यमिता को हतोत्साहित करके अपने समाजवादी अतीत से दूर जाने की दिशा में बदलाव को उलट सकता है। जीएसटी अनुपालन को मजबूत करना आवश्यक है, क्योंकि कई सामान अभी भी इसके दायरे से

बाहर हैं। आयकर प्रणाली को सुव्यवस्थित और सरल बनाने से कार्यकुशलता बढ़ सकती है, कर आधार व्यापक हो सकता है और करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम हो सकता है। विलासिता उपभोग कर लागू करने से उच्च-स्तरीय वस्तुओं और सेवाओं को लक्षित किया जा सकता है, जिससे आम जनता पर बोझ डाले बिना असमानता को सम्बोधित करते हुए राजस्व उत्पन्न हो सकता है।

संपत्ति कराधान पर बहस जटिल है, जिसमें कर चोरी और पूंजी पलायन जैसी चुनौतियों के साथ असमानता को कम करने की क्षमता को संतुलित करना शामिल है। जबकि यह सामाजिक कार्यक्रमों के लिए संसाधन उत्पन्न कर सकता है, भारत में कार्याव्ययन संपत्ति और प्रशासनिक लागतों की प्रकृति के कारण जटिल है। इंकटी और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

–डॉ. सत्यवान सौरभ

1840 में इस तरह का कर पेश किया था। अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया, जिसमें 1892 में नीदरलैंड और 1911 में स्वीडन शामिल हैं। भारत 1957 में इस सूची में शामिल हुआ जब वित्त मंत्री टी-टी कृष्णामाचारी ने संपत्ति कर लागू किया। हालाँकि, समय के साथ इस कर को लागू करने वाले देशों की संख्या कम हो गई है। उदाहरण के लिए कर लगाने वाले देशों की संख्या 1990 में 12 से घटकर 2017 में चार रह गई। भारत ने 2015 में इसे समाप्त कर दिया।

हाल के वर्षों में धन असमानता पर बढ़ती चिंताओं के कारण धन पर कर लगाने का विचार फिर से सामने आया है। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत में असमानता में तेज वृद्धि को उजागर किया गया है, खासकर 2014-15 के बाद। उनके शोध से संकेत मिलता है कि शीर्ष 1% आय अर्जित करने वाले के पास 2022-23 में देश की आय का

22.6ब और इसकी संपत्ति का 40.1% हिस्सा होगा-यह आंकड़ा दक्षिण अफ्रीका, बाजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से भी अधिक है। पिकेटी और उनके सह-लेखक 10 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध संपत्ति पर 2% वार्षिक कर और उसी सीमा से अधिक की संपत्ति पर 33ब कर का प्रस्ताव करते हैं।

धन करों की अपील के बावजूद उनका कार्याव्ययन कठिनाइयों से भरा है। 1985 में जब वित्त मंत्री वीपी सिंह ने संपदा शुल्क (विरासत कर) को समाप्त किया, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रशासन महंगा था और इसकी राजस्व प्राप्ति न्यूनतम थी, जिसमें केवल लगभग 20 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। सिंह ने स्वीकार किया कि कर धन असमानता को कम करने और राज्य विकास योजनाओं का समर्थन करने के अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। इसी तरह, जब 2015 में संपत्ति कर को समाप्त कर दिया गया, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2013-14 में

सर्पाफा बाजार में तेजी से महंगा हुआ सोना, चांदी की भी बड़ी चमक

एजेंसी नई दिल्ली। घरेलू सर्पाफा बाजार में आज तेजी का रुख नजर आ रहा है। सोने के भाव में तेजी आने की वजह से देश के ज्यादातर सर्पाफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 77,600 रुपये से लेकर 77,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 71,150 रुपये से लेकर 71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी की कीमत में भी आजा मामूली तेजी आने के कारण दिल्ली सर्पाफा बाजार में इसकी कीमत 91,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज 77,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 71,150 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 77,450 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रेटिल कीमत 77,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 71,050 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 77,450 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 77,450 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

अडानी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया

मुंबई। जाने माने उद्योगपति और अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री अडानी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने शोक संदेश में लिखा, इतिहास 1991 के आर्थिक सुधारों में डॉ. मनमोहन सिंह की महती भूमिका के लिए उन्हें हमेशा सम्मान देता। उनके सुधारवादी कदमों से भारत को एक नया रूप मिला और देश ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलें। डॉ. सिंह अपनी विशिष्ट नेतृत्व क्षमता, विनम्रता और देश सेवा से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे।। पूर्व प्रधानमंत्री का आज देर शाम राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। वह 92 वर्ष के थे।

फियो की अमेरिका केंद्रित 750 करोड़ रु की विपणन योजना की सिफारिश

नयी दिल्ली। देश के निर्यातकों के शीर्ष फोरम फियो ने अमेरिका और चीन के बीच व्यापार में आयात प्रशुल्क की संभावित लड़ाई के बीच भारतीय निर्यात क्षेत्र के अवसर बढ़ाने के लिये सरकार को अमेरिकी बाजार पर केंद्रित करते हुये 750 करोड़ रुपये की तीन साल की विशेष विपणन योजना शुरू करने का सुझाव दिया है। फियो का मानना है कि इससे भारत को तीन वर्ष में दो लाख करोड़ रुपये के निर्यात के अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं। फियो अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने बजट से पहले सरकार के समक्ष निर्यात क्षेत्र के लिये सिफारिशों की विस्तृत सूची प्रस्तुत की है। फियो ने आंतरिक अध्ययन के आधार पर कहा है, + टैरिफ (प्रशुल्क) युद्ध से भारत के निर्यात के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। चीन पर उच्च टैरिफ लगाने का इरादा रखने वाला अमेरिका भारतीय निर्यात के लिये एक महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां चीन पहले एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। फियो अध्यक्ष ने अपनी प्रस्तुति में कहा है, हमें इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनियों में भाग लेने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपये (कुल मिलाकर 750 करोड़ रुपये) के कोष के साथ अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विपणन योजना शुरू की जा सकती है, जिससे तीन वर्षों में 2,00,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात हो सके।

दो वर्षों में तीन हजार ज्वेलरी स्टोर शुरू करने की उद्योग की योजना: शाह

नयी दिल्ली। जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेपीसी) के अध्यक्ष विपुल शाह ने आज कहा कि पिछले बजट में कीमती धातुओं पर आयात शुल्क कम करने से इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा मिला है और यह परिवार द्वारा संचालित आपूर्ण व्यवसायों की कई कंपनियों के शेयर बाजार सूचीबद्ध होने से लेकर विदेशों में प्रमुख खुदरा विक्रेताओं के विस्तार और अगले दो वर्षों में 3,000 खुदरा दुकानों के खुलने की योजना से स्पष्ट है, जिससे देश भर में लाखों रोजगार के अवसर पैदा हों।। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आज यहां बजट पूर्व चर्चा में भाग लेने के बाद श्री शाह ने यहां जारी बयान में कहा कि इस दौरान उन्होंने रत्न एवं आपूर्ण उद्योग की ओर से प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जिनका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और उद्योग की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना था। उन्होंने कहा हम पिछले बजट में कीमती धातुओं पर आयात शुल्क कम करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं, एक ऐसा कदम जिसने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा दिया है।

क्राईट प्यूचर टेक को रेलवे से कवच सिस्टम के लिए 978.61 करोड़ रुपये का ऑर्डर

एजेंसी नई दिल्ली/मोहाली। रेलवे सुरक्षा और ट्रेन कंट्रोल एबेडेड सिस्टम पर काम करने वाली एक शोध-उन्मुख कंपनी क्राइंट प्यूचर टेक लिमिटेड (क्राईंट) ने एक बड़ा ऑर्डर मिलने का ऐलान किया है। कंपनी के ट्रेन कंट्रोल सिस्टम डिवीजन ने भारतीय रेलवे और चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) से 978.61 करोड़ रुपये (कर सहित) का अनुबंध हासिल किया है, जिसमें 1,200 इंजनों पर कवच सिस््टम लगाना और चालू करना है।

क्राईंट प्यूचर टेक लिमिटेड (क्राईंट) के ट्रेन कंट्रोल सिस्टम डिवीजन ने जारी एक बयान में कहा कि उसे 1,200 लोकोमोटिव पर कवच सिस्टम लगाने और चालू

करने के लिए भारतीय रेल और चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) द्वारा 978.61 करोड़ रुपये (करों सहित) का, प्रतिष्ठित अनुबंध दिया गया है। ये परिशिष्टता क्राइंट का अब तक का सबसे बड़ा अनुबंध है, जो सुरक्षा नवाचारों को आगे बढ़ाने और भारत के रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

क्राईंट प्यूचर टेक के प्रबंध निदेशक मोहित वोहरा ने कहा कि यह उपलब्धि महत्वपूर्ण रेलवे सुरक्षा प्रणालियों के विकास और कार्यान्वयन क्षमताओं में क्राइंट के समर्पण, नवाचार और विशेषज्ञता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कवच प्रणाली के विकास की हमारी यात्रा अगस्त 2020 में शुरू हुई, जो

का शिकार हो गए। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.39 अंक की सांकेतिक कमजोरी के साथ बंद हुआ। दूसरी ओर, निफ्टी ने 0.10 प्रतिशत की बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया।

आज दिन भर के कारोबार में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। इसके साथ ही कैपिटल गुड्स, कंज्यूम ड्यूरेबल, हेल्थ

अमित शाह ने की भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

एजेंसी नई दिल्ली।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ और किसानों को समृद्ध बनाने के विजन को साकार करने की दिशा में भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बैठक में बीबीएसएसएल द्वारा वर्ष 2025-26 में और 20,000 समितियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा। शाह ने कहा कि बीबीएसएसएल को बीज उत्पादन के लिए पानी और कीटनाशक के उपयोग को कम करने

नवंबर में एनएसई से जुड़े 15.2 लाख नए निवेशक, इनवेस्टर्स की कुल संख्या 10.7 करोड़ के पार

एजेंसी नई दिल्ली। अक्टूबर और नवंबर में घरेलू शेयर बाजार में आई गिरावट के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर रजिस्टर होने वाले निवेशकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में एनएसई से कुल 15.20 लाख नए निवेशक जुड़े, जो पिछले 7 महीने का सबसे निचला स्तर है। हालांकि एनएसई पर रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या नवंबर के महीने तक 10.72 करोड़ हो गई थी। इस साल फरवरी में रजिस्टर्ड निवेशकों की संख्या 9 करोड़ से कुछ अधिक थी, जो अगस्त तक 10 करोड़ हो गई थी। एनएसई की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर में बाजार में आई गिरावट की वजह से नए निवेशकों के रजिस्ट्रेशन में गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन वार्षिक आधार पर देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इसमें बढ़ोतरी हुई है। 1 साल पहले नवंबर की महीने में निवेशकों के रजिस्ट्रेशन का ये आंकड़ा 13.4 लाख था, जो

सीतारमण ने निर्यात और व्यापार उद्योग विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व बैठक में की सुझाव एकत्र करने पर चर्चा

एजेंसी नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजधानी में निर्यात, व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इस बैठक में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अंतर्दृष्टि और सुझाव एकत्र करने पर चर्चा हुई।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को संसद में अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी।

निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी बजट में व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ और मुख्य



क्षेत्र के विशेषज्ञों से बैठक की थी। इस बैठक में केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए उनके विचार और सुझाव मांगे गए। सीतारमण के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रह्ण्यम, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंथा नागेश्वरन और सुरजीत भल्ला, डीके जोशी समेत जने-माने अर्थशास्त्री भी बैठक में शामिल थे।

पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों की उपज उच्चतम हो और उनकी फसल की



परिपक्वता की अवधि अधिक हो इस दिशा में काम करे। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि बीबीएसएसएल भारत के परंपरागत ‘मोटे’ बीजों के संग्रहण और संरक्षण की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इफ्को और कृषकों को हमारे मूल और हाइब्रिड बीजों का

पोषक तत्वों की दृष्टि से मूल्यवान करना चाहिए। शाह ने कहा कि पारंपरिक ‘मोटे’ या लुप्तप्राय बीजों के संवर्धन व संरक्षण



के साथ-साथ पोषक तत्वों को कम किए बिना दहन और तिलहन के बीजों का उत्पादन बढ़ाना बीबीएसएसएल की प्राथमिकता रहनी चाहिए। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने बीज उत्पादन बढ़ाने से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 10 साल का रोडमैप बनाने और उसकी निरंतर समीक्षा करने पर बल दिया।

माह नवंबर 2024 में सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 401.32 रहा

एजेंसी जयपुर। राज्य का माह नवंबर, 2024 को सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1999-2000) पर गत माह की तुलना में 0.82 प्रतिशत की कमी के साथ 401.32 रहा। माह नवंबर, 2024 में प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक 457.69 एवं ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह सूचकांक 568.11 तथा वित्तिमित उत्पाद समूह सूचकांक 308.62 अंक रहा है। राज्य के मासिक सामान्य थोक मूल्य सूचकांक के आधारित मूद्रास्फीति नवंबर, 2024 में गत वर्ष नवम्बर माह की तुलना में 2.54 प्रतिशत रही है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव विनेश सिंघवी ने बताया कि माह नवंबर, 2024 में प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक गत माह की तुलना में 2.04 प्रतिशत की कमी के साथ 457.69 रहा है। प्राथमिक वस्तु समूह के सूचकांक में कमी का प्रमुख कारण इसके अंतर्गत कृषि उप समूह सूचकांक में 2.19



दिसंबर की मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक एनएसई में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 2021-22 में कुल रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स में 22 प्रतिशत महिलाएं थीं लेकिन नवंबर 2024 तक महिलाओं की भागीदारी 24 प्रतिशत हो चुकी है। इसी तरह एनएसई पर रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स की औसत आयु 35.8 साल है। इसके अलावा कुल इन्वेस्टर्स में 30 साल से कम आयु के निवेशकों की संख्या 39.9 प्रतिशत है।

आर्थिक वृद्धि को बनाये रखने की आवश्यकता, तीसरी तिमाही होगी बेहतर: वित्त मंत्रालय

एजेंसी नई दिल्ली। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक वृद्धि को बनाये रखने के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करने की जरूरत होगी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में नरमी के बाद तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) का परिदृश्य बेहतर दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्रालय की नवंबर 2024 की जारी मासिक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। वित्त मंत्रालय ने नवंबर महीने की जारी अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में नरमी आई है, जो कम होकर 5.4 फीसदी पर रही है। मंत्रालय ने कहा कि दूसरी तिमाही में नरमी के बाद तीसरी तिमाही का परिदृश्य बेहतर दिखाई दे रहा है।

में प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सहकारी संस्थाओं को सभी किसानों को प्रमाणित बीज से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि देशभर के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 20,000 से अधिक विभिन्न सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की शेरधारक है। अमित शाह ने कहा कि बीबीएसएसएल को बीज उत्पादन, शोध और संवर्धन की दिशा में काम करने वाले सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं का उपयोग करना चाहिए। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने बीज उत्पादन बढ़ाने से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 10 साल का रोडमैप बनाने और उसकी निरंतर समीक्षा करने पर बल दिया।

माह नवंबर 2024 में सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 401.32 रहा

एजेंसी जयपुर। राज्य का माह नवंबर, 2024 को सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1999-2000) पर गत माह की तुलना में 0.82 प्रतिशत की कमी के साथ 401.32 रहा। माह नवंबर, 2024 में प्राथमिक वस्तु समूह सूचकांक 457.69 एवं ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह सूचकांक 568.11 तथा वित्तिमित उत्पाद समूह सूचकांक 308.62 अंक रहा है। राज्य के मासिक सामान्य थोक मूल्य सूचकांक के आधारित मूद्रास्फीति नवंबर, 2024 में गत वर्ष नवम्बर माह की तुलना में 2.54 प्रतिशत रही है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव विनेश सिंघवी ने बताया कि माह नवंबर, 2024 में प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक गत माह की तुलना में 2.04 प्रतिशत की कमी के साथ 457.69 रहा है। प्राथमिक वस्तु समूह के सूचकांक में कमी का प्रमुख कारण इसके अंतर्गत कृषि उप समूह सूचकांक में 2.19

आरबीआई ने एआई के नैतिक उपयोग पर 8 सदस्यीय पैनल किया गठित

एजेंसी मुंबई/नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जिम्मेदार एवं नैतिक इस्तेमाल के बारे में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ये समिति पहली बैठक की तारीख से छह महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर पुष्पक भट्टचार्य इस समिति के अध्यक्ष होंगे। भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली यह पैनल वैश्विक स्तर के साथ-साथ भारत में वित्तीय सेवाओं में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करेगा। यह समिति वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई पर विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करेगी। यह पैनल एआई से जुड़े संभावित जोखिमों की पहचान करके परिणामी अनुपालन आवश्यकताओं की सिफारिश करेगा। यह समिति भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एआई मॉडल या अनुप्रयोगों को जिम्मेदारीपूर्वक नैतिक रूप से अपनाने के लिए शासन संबंधी पहलुओं सहित एक रूपरेखा की सिफारिश करेगी। आरबीआई ने कहा कि इस समिति में देवजानी घोष (स्वतंत्र निदेशक, रिजर्व बैंक इनेवेशन हब), बलरामन रवींद्रन (प्रोफेसर और प्रमुख, वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई, आईआईटी मद्रास), अभिषेक सिंह (अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) शामिल हैं। इनके अलावा राहुल मथन (साझेदार, ट्राइलोगल), अंजनी राठौर (समूह प्रमुख और मुख्य डिजिटल अनुभव अधिकारी, एनबीएफसी बैंक), हरि नागरालू (सुस्था एआई अनुसंधान प्रमुख, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया) और सुवेंदु पति (मुख्य महाप्रबंधक, वित्त प्रौद्योगिकी, आरबीआई) को सदस्य बनाया गया है।

माह नवंबर 2024 में सभी वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक 401.32 रहा

प्रतिशत एवं खनिज उप समूह सूचकांक में 0.95 प्रतिशत की कमी दर्ज होना रहा है। उन्होंने बताया कि आलोच्य माह में प्राथमिक वस्तु



समूह में कृषि मद समूह के सूचकांक के अन्तर्गत दालों में 3.85 प्रतिशत, फलों में 52.71 प्रतिशत, सब्जियों में 10.13 प्रतिशत, रेशा में 0.20 प्रतिशत, तिलहन में 1.58 प्रतिशत एवं अन्य अखाद्य पदार्थों में 5.75 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

खनिज उप समूह सूचकांक के अंतर्गत आलोच्य माह में 0.95 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। जिसमें मुख्यतः जिप्सम में 2.08 प्रतिशत, चूना पत्थर में 0.49 प्रतिशत एवं चांदी में 19.51 प्रतिशत की कमी

आर्थिक वृद्धि को बनाये रखने की आवश्यकता, तीसरी तिमाही होगी बेहतर: वित्त मंत्रालय

आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को 4.5 फीसदी से घटकर चार फीसदी कर दिया। इससे कर्ज वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जो वित्त वर्ष 2024-25 में कुछ ठोस हुई है। रिपोर्ट के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 2025-26 को देखा जाए तो नई अनिश्चितताएं सामने आई हैं और वैश्विक व्यापार वृद्धि पहले की तुलना में अधिक अनिश्चित दिख रही है। पीएमआई के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर और नवंबर महीने के आंकड़े यह बताते हैं कि कंपनियों के नए ऑर्डर में वृद्धि हो रही है और मांग मजबूत है। इसके साथ ही ये विस्तार कर रहे हैं। यह रिपोर्ट कहती है कि सरकारी पूंजीगत व्यय में अपेक्षित वृद्धि से सीमेंट, लोहा, इस्पात, खनन और बिजली क्षेत्रों को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

आरआईएनएल को मिला आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण का स्वर्ण पुरस्कार

एजेंसी नई दिल्ली। वषाखापतनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने आंध्र प्रदेश (एपी) ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2024 में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। आरआईएनएल को पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार विशाखापतनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई आरआईएनएल ने लौह और इस्पात श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण पहल के लिए राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिताओं में प्रतिष्ठित %गोल्ड अवार्ड% जीता है। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में विजयवाड़ा में आयोजित ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के समानान समारोह में आंध्र प्रदेश सरकार के

विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) के. विजयानंद, आईएसएस से आरआईएनएल की ओर से उत्तम ब्रह्मा, महाप्रबंधक (ऊर्जा, पर्यावरण एवं

को पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने तथा अपरिष्ठा ऊर्जा का दोहन करने के लिए दिया गया। आरआईएनएल के



उपयोगिताएं) आरआईएनएल और वीवीवीएस पुल्ला रेड्डी, उप-महाप्रबंधक (ऊर्जा प्रबंधन विभाग) आरआईएनएल ने स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया।इस्पात मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार आरआईएनएल

सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) एके सक्सेना ने विशाखापतनम इस्पात संयंत्र के ऊर्जा प्रबंधन तथा सहायक विभागों को आरआईएनएल को एक बार फिर गौरव दिलाने के लिए बधाई दी।

शुरुआती उतार-चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी

को आज के कारोबार से करीब 37 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया।आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,074 शेयरों में एंक्विट ट्रेडिंग हुई।

इनमें 1,640 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,327 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 107 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,504 शेयरों में एंक्विट ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,010 शेयर मुनाफा कमा कर हरे

निशान में और 1,494 शेयर नुकसान उठ कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 13 शेयर बढ़त के साथ और 17 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 30 शेयर हरे निशान में और 20 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 84.41 अंक की मजबूती के साथ 78,557.28 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होते ही

खरीदारी के सपोर्ट से ये सूचकांक 425.50 अंक की मजबूती के साथ 78,898.37 अंक तक पहुंच गया, लेकिन इसके बाद बिकवाली का दबाव बनने की वजह से इस सूचकांक में गिरावट आ गई। लगातार हो रही बिकवाली के कारण दोपहर 11 के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक ऊपरी स्तर से करीब 725 अंक लुढ़क कर 299.49 अंक की कमजोरी के साथ 78,173.38 अंक तक गिर गया।

घात लगाकर किए गए हमले में 14 अंतरिम सरकारी अधिकारियों की मौत

एजेंसी दमिश्क । सीरिया के अंतरिम आंतरिक मंत्रालय के 14 अधिकारी उत्तर-पश्चिमी प्रांत टार्टस में एक विश्वासघाती हमले में मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी आंतरिक मंत्री मोहम्मद अब्दुल रहमान ने दी। स्थानीय अल-वतन अखबार के हवाले से सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री ने हमलावरों को पूर्व सरकार के अवशेष बताया। मंत्रालय ने कहा कि मारे गए अधिकारी सुरक्षा बनाए रखने और नागरिकों की रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इससे पहले, यह रिपोर्ट किया गया था कि टार्टस प्रांत में हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन और स्थानीय सशस्त्र निवासियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़ाई खारबेट अल-मजजा गांव में तब शुरू हुई, जब स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों द्वारा उनके घरों की जांच का विरोध किया, जिसके बाद सशस्त्र निवासियों ने एचटीएस से जुड़े एक वाहन में आग लगा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन्य गठबंधन की यूनिट 82 और के9 दस्तों का एक बड़ा काफिला लताकिया प्रांत के पास के क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।

अमेरिका के कैलिफोर्निया में बर्ड फ्लू का प्रकोप, राज्य में दूध उत्पादन में भारी गिरावट

सैक्रामेंटो। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एवियन इन्फ्लुएंजा ए (एच5एन1) वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैलिफोर्निया के अधिकारियों के अनुसार, बर्ड फ्लू ने अगस्त से अब तक 984 डेयरियों में से 659 को प्रभावित किया है। इनमें से एक-चौथाई मामले पिछले महीने में ही सामने आए। समाचार एजेंसी के अनुसार, राज्य के डेयरी उद्योग में तेजी से फैल रहे इस वायरस के कारण गवर्नर गैविन न्यूसम ने राज्य में पिछले सप्ताह आपातकाल की घोषणा की थी। कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम ने एक बयान में कहा, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी एजेंसियों के पास इस विषम स्थिति से सामना करने का जरूरी संसाधन किताना है जिससे वो परिस्थिति के अनुरार तुरंत रिएक्ट कर सकें। अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) की जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, इस महामारी का मानवीय प्रभाव लगातार गंभीर होता जा रहा है, तथा कैलिफोर्निया में ऐसे 36 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। जो कि देश के कुल 65 मामलों के आधे से भी अधिक हैं, हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में स्थानीय स्तर पर पुष्टि के मामले संघीय आंकड़ों में अभी तक जुड़े नहीं हैं।

नेतन्याहू ने हूती विद्रोहियों को दी चेतावनी, बोले इजरायल हवाई हमला करने पर कर रहा विचार

यरूशलम । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि यमन में हूती बलों को भी इजरायल विरोधी समूहों जैसा ही परिणाम भुगताना पड़ेगा। नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा, हूती विद्रोहियों को भी वही सबक मिलेगा जो हमस, हिजबुल्लाह, असद सरकार और दूसरों को मिला है। हालांकि, इसमें समय लग सकता है। लेकिन, यह पूरे मध्य पूर्व के लिए एक सबक साबित होगा। इससे पहले बुधवार को हूती विद्रोहियों ने लगातार दूसरे दिन इजरायल की ओर जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल दागी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार एक ड्रोन दक्षिणी इजरायल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कथित तौर पर हूती बलों द्वारा जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजरायल यमन में हूती बलों के खिलाफ एक बड़े हमले पर विचार कर रहा है। इजरायल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी ने बताया कि सेना एक संभावित ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से कान टीवी ने कहा कि इजरायली वायु सेना, सैन्य खुफिया और संचालन निदेशालय पिछले सप्ताह के हमले के बाद यमन में काफी आक्रामक योजनाएं बना रहे हैं और टारगेट सूची का विस्तार कर रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर से हूती समूह ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजरायल पर कभी-कभी मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इसके जवाब में इजरायल ने कई बड़े हवाई हमले किए, जिनमें से सबसे हाल ही में पिछले सप्ताह हुआ। इस हमले में नौ लोगों की मौत हो गई।

इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए 23 फिलिस्तीनी

गाजा । फिलिस्तीनी सूत्रों ने बताया कि गाजा पट्टी में इजरायली हवाई हमलों में 22 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा में सिविल डिफेंस के प्रवक्ता महमूद बसल ने सिन्हुआ को बताया कि इजरायली विमानों ने बुधवार को उत्तरी गाजा शहर में अल-मुब्बन स्कूल के अंदर विस्थापित व्यक्तियों के लिए बने टेंट को निशाना बनाया। बसल ने बताया कि नागरिक सुरक्षा दल ने इजरायली हमलों के बाद स्कूल से सात शव और 25 घायल व्यक्तियों को बरामद किया, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। स्थानीय सूत्र और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टेंट में आग लग गई और बमबारी में कुछ शव क्षत-विक्षत हो गए। इजरायली सेना ने एक प्रेस बयान में कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए इजरायली वायु सेना के एक विमान ने गाजा शहर के अल-फुरकान इलाके में हमस के एक सदस्य को निशाना बनाया। दावा किया गया कि सेना ने पूरी सावधानी बरती। आम नागरिकों को ध्यान में रख हमले किए गए।

दक्षिण कोरिया में अब विपक्ष का कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ मोर्चा

एजेंसी सियोल। दक्षिण कोरिया में अब विश्व ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुख्य विपक्षी दल केओकेटिक पार्टी ऑफ कोरिया (डीपीके) ने हान पर संवैधानिक न्यायालय में खाली तीन जजों के पदों पर नियुक्ति पर आनाकानी का आरोप लगाया है। साथ ही महाभियोग का सामना करने के लिए चेताया है।

दक्षिण कोरिया के दो प्रमुख समाचार पत्रों द कोरिया टाइम्स और द कोरिया हेराल्ड ने अपनी खबर में इस विवाद पर विस्तार से चर्चा की है। दरअसल कार्यवाहक राष्ट्रपति हान ने कहा है कि वह तब तक संवैधानिक न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करेंगे जब तक प्रतिद्वंद्वी पार्टियां राजनीतिक समझौता

नहीं कर लेतीं। उनके इस बयान के बाद डीपीके ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव



पेश कर नेशनल असेंबली के पूर्ण सत्र में इसकी सूचना दी। डीपीके की मांग है कि नौ सदस्यीय संवैधानिक न्यायालय के तीन खाली पदों पर

कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्ति को मंजूरी दें। दरअसल संवैधानिक न्यायालय को यह तय करना है कि

तीन दिसंबर की अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषणा पर राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ पारित हो चुके महाभियोग प्रस्ताव को चलाया जा सकता है या नहीं। देश के संविधान के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव को बरकरार रखने के लिए संवैधानिक न्यायालय में कम से कम छह मतों की आवश्यकता होती है। मुख्य विपक्षी दल डीपीके ने नेशनल असेंबली के पूर्ण सत्र के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान करने की रणनीति तैयार की है। कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू ने साफ कहा कि वह द्विदलीय समझौते के बिना किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करेंगे। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने हान पर महाभियोग चलाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मार्शल लॉ की अल्पकालिक घोषणा का सहयोगी बताया गया।



डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित प्रमुख नेताओं ने जताया शोक

एजेंसी काठमांडू। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रमुख दल के नेताओं ने शोक प्रकट किया है। इन सभी नेताओं ने दिवंगत मनमोहन सिंह के साथ अपनी स्मृति को साझा किया।



नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने एक बयान जारी करते हुए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर दुःख प्रकट किया है। डॉ. सिंह को विश्व के प्रख्यात अर्थशास्त्री बताते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि उनके द्वारा भारत के लिए अपनाई गई अर्थनीति का नेपाल समेत कई देशों ने अनुसरण करते हुए लाभ लिया है। राष्ट्रपति ने शोक संदेश भेजते हुए नेपाल की जनता की तरफ से गहरी शोक संवेदना जताई है।

सीरिया में अपदस्थ राष्ट्रपति के 20 से अधिक समर्थक मारे गए, कम से कम 45 गिरफ्तार

एजेंसी दमिश्क। सीरिया में अब अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल-असद के समर्थकों की जान पर बन आई है। सैन्य संचालन विभाग ने राजधानी दमिश्क, ग्रामीण इलाकों, होम्स, लताकिया और टार्टस के कई इलाकों में अभियान चलाकर असद के 20 से अधिक समर्थकों को मार गिराया और कम से कम 45 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीरियाई सैन्य संचालन विभाग असद के इन समर्थकों को आतंकवादी मान रहा है। न्यूज एजेंसी ‘963+’ के अनुसार सैन्य संचालन विभाग के करीबी सूत्र ने बताया कि मेजेह 86, रिपब्लिकन गार्ड के अलावा, दमिश्क के डुम्मर प्रोजेक्ट, कुत्सया, अल-हमा और असल अल में सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। सैन्य संचालन

अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और माओवादी पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचण्ड ने डॉ. सिंह के निधन के लिए शोक संदेश में लाने में डॉ. मनमोहन की भूमिका की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्बहाली में डॉ. मनमोहन सिंह के ही मार्गदर्शन में सात दल और तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी के बीच लिखित समझौता हुआ था।

इसी तरह माओवादी के पूर्व नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. बाबुराम भट्टराई ने मनमोहन सिंह के निधन पर अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए उन्हें एक महान

अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक, दक्षिण एशिया के उदारीकरण के अग्रणी नेता के रूप में याद किया है। भट्टराई ने कहा कि नेपाल-भारत संबंधों को लेकर अत्यंत ही सकारात्मक रहने वाले डॉ. मनमोहन सिंह के निधन से नेपाली जनता को भी उतना ही दुःख हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल ने डॉ. सिंह के निधन पर जारी शोक संदेश में उन्हें नेपाल का सच्चा मित्र, सच्चे शुभचिंतक और नेपाल तथा नेपाली जनता के प्रति हमेशा ही प्रेम और सद्भाव रखने वाले नेता के रूप में याद किया है। माधव नेपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें डॉ. मनमोहन सिंह के साथ कई बार मिलने और मंच साझा करने का मौका मिला है। उनके निधन से न सिर्फ भारत ने बल्कि पूरे विश्व ने एक महान अर्थशास्त्री को खो दिया है।

चीन का ब्रह्मपुत्र नद पर सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान

एजेंसी बीजिंग। चीन ने भारतीय सीमा के करीब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 137 अरब डॉलर की लागत से दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे तटवर्ती देशों- भारत और बांग्लादेश में चिंताएं बढ़ गई हैं।

दरअसल, चीन की सरकार ने ऐलान किया है कि वह तिब्बत की सबसे लंबी नदी यारलुंग त्संगपो (भारत का ब्रम्हपुत्र नद) पर महाशक्तिशाली बांध बनाने जा रही है। इस बांध से चीन के धरती की स्पीड को प्रभावित करने वाले धीे जॉर्ज बांध से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा होगी। चीन की सरकारी न्यूज

एजेंसी सिन्हुआ ने यह जानकारी दी है। एजेंसी के अनुसार, चीन की



सरकार इसे हिमालय के करीब एक विशाल घाटी में बनाने की योजना

पर काम कर रही है। इसी स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और

यह बीजिंग के लिए इंजीनियरिंग की बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। सरकार इस बात को नजाने के लिए 137 अरब डॉलर खर्च करने जा रही है।

बांध निर्माण की घोषणा के बाद कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह चीनी बांध धरती पर चल रहे सिंगल इन्फ्रास्ट्रक्चर के किसी भी प्राजेक्ट को बहुत पीछे कर देगा जबकि कुछ विशेषज्ञ इस निर्णय को सोची समझी प्रक्रिया बता रहे हैं। उनका कहना है कि चीन इस दैत्यवार बांध का इस्तेमाल हथियार की तरह उपयोग कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कभी भी बाढ़ ला सकता है।

पाकिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों में 13 आतंकवादी ढेर

एजेंसी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिम खैबर पख्तुनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों ने तीन अलग-अलग अभियानों में एक सैन्य अधिकारी और 13 आतंकवादियों को मार गिराया। एजेंसी सिन्हुआ ने सेना के मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के हवाले से बताया कि बन्नु जिले में एक ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों के ठिकाने को सटीक रूप से निशाना बनाया गया और मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मार गिराए गए। बयान में कहा गया है कि उत्तरी वजीरिस्तान जिले में एक और ऑपरेशन हुआ, जिसमें भारी गोलीबारी के दौरान एक सैन्य अधिकारी और पांच आतंकवादी मारे गए। इसके अलावा, आठ आतंकवादी घायल भी हुए। बयान में कहा गया है कि तीसरी मुठभेड़

दक्षिण वजीरिस्तान जिले में हुई, जिसमें छह आतंकवादी मारे गए और आठ अन्य घायल हो गए। आईएसपीआर ने कहा कि इलाके में



मौजूद बाकी आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए अभियान जारी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि दिसंबर में पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में पुलिस ने एक आतंकवादी हमले को विफल कर दिया था, जिसमें चार आतंकवादी मारे गए थे और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जिले की पुलिस ने एक बयान में कहा

कि यह घटना मियांवाली जिले में हुई, जहां लगभग 20 आतंकवादियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। स्टेशन के अंदर पुलिस सतर्क थी और उसकी जल्दी प्रतिक्रिया की वजह से, आतंकवादियों की साजिश नाकाम हो गई और वे घटनास्थल से भाग गए। बयान में कहा गया कि हमले के बाद दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी पहचान की जांच की जा रही है।

सीरिया के अंतरिम अधिकारियों ने दमिश्क के उपनगरीय इलाके, टारटस में अभियान शुरू किया

एजेंसी दमिश्क। सीरिया के अंतरिम प्रशासन ने ग्रामीण दमिश्क में सुरक्षा अभियान शुरू किया। साथ ही तटीय प्रांत टारटस में सशस्त्र समूहों को निशाना बनाकर अभियान चलाया, स्थानीय मीडिया अल-वतन ऑनलाइन ने यह जानकारी दी। अभियान ने दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में कुत्सया, अल-हमे, ऐश अल-वाीर, जबल अल-बाई और हे अल-वुरूद सहित पड़ोस को निशाना बनाया। अस-वन ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि अभियान का उद्देश्य अवैध हथियारों को जब्त करके और कलह भड़काने वाले के रूप में पहचाने गए व्यक्तियों को हिरासत में लेकर क्षेत्र की तलाशी लेना था। इस बीच, टार्टस में, अधिकारियों ने घोषणा की कि उन्होंने कई लड़कों को निष्प्रभावी कर दिया है, जिन्हें उन्होंने जंगली इलाकों और



जारी है। समाचार एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई देश भर में सुरक्षा पहलों की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य ग़प नेतृत्व के अधिकार को मजबूत करना है। यह घटना टार्टस, लताकिया, होम्स और दमिश्क में प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों पर उतरने के एक दिन बाद हुई, जिसमें अलावी अल्पसंख्यक के धार्मिक स्थल पर कथित हमलों की निंदा की गई। सुरक्षा अधिकारियों ने जोर देकर कहा

कि ऐसी घटनाएं अलग-थलग हैं और चेतावनी दी कि पूर्व शासन के अवशेष सांप्रदायिक विभाजन का फायदा उठाकर कलह पैदा कर सकते हैं , यह बताया गया कि सीरिया के अंतरिम आंतरिक मंत्रालय के 14 अधिकारी उत्तर-पश्चिमी प्रांत टार्टस में एक ‘विश्वासघाती हमले’ में मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। अंतरिम सरकार के आंतरिक मंत्री मोहम्मद अब्दुल रहमान ने हमलावरों को पूर्व सरकार के ‘अवशेष’ बताया। मंत्रालय ने कहा कि मारे गए अधिकारी सुरक्षा बनाए रखने और नागरिकों की रक्षा करने के उद्देश्य से कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में सीरिया में बशर अल-असद की सरकार के हाल ही में पतन के बाद, कई हाई-प्रोफाइल घटनाओं ने पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है।

सोवियत संघ और अमेरिका से सबक ले इस्लामाबाद : पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पर तालिबान की चेतावनी

एजेंसी काबुल । इस्लामाबाद को अफगानिस्तान पर निशाना साधने से पहले इतिहास से सबक सीखना चाहिए, पाकिस्तान को यह चेतावनी अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमिर खान मुताली ने दी। कई रिपोर्टों में मुताली के हवाले से कहा गया है कि अफगानिस्तान अपने क्षेत्र पर हुए आक्रमण को नहीं भूलेगा, और पाकिस्तानी शासकों को एक संतुलित नीति अपनानी चाहिए।

यह बात उन्होंने गुरुवार दोपहर सोवियत आक्रमण की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। अपने भाषण के दौरान विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग्य से सीखने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान कभी भी आक्रमणों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के लोगों से अपने शासकों की गलत नीतियों को रोकने की अपील भी की। मुताली की यह कड़ी प्रतिक्रिया अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के 48 घंटे से भी कम समय बाद आई है, जिसमें मंगलवार रात कई महिलाओं और बच्चों सहित 46 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक पकिंका प्रांत के बरमल जिले के कुछ हिस्सों में की गई। यह इस साल दूसरी बार है इस्लामाबाद की तरफ अफगान के ‘नागरिक क्षेत्रों’ पर सीधे मिसाइ्री अटैक किया गया है।

एजेंसी ओस्लो । नॉर्वे के उत्तरीय शहर हैडसेल में एक यात्री बस के झील में गिर जाने से तीन लोगों की मौत हो गई जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह जानकारी देश के स्थानीय अधिकारियों ने दी। झील में गिरने के समय इस बस में 50 से अधिक यात्री सफर कर रहे थे। दुर्घटना से पहले यह बस नार्विक से स्वोलेवर जा रही थी। स्वोलेवर जाते समय

बस उत्तरी नॉर्वे के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लोफोटेन द्वीपसमूह के राफ्टसूंडेट के निकट होटल में पलट गई। समाचार एजेंसी के अनुसार, आपातकालीन सेवाओं को घटनास्थल के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खराब मौसम की वजह से घटनास्थल पर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर को ले जाने में भी समस्या हुई। नॉर्डलैंड पुलिस डिप्ट्रिक्ट के चीफ ऑफ स्टोप बेट



एरे एलर्टसन ने इस दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, बस आंशिक रूप से पानी में डुबी हुई है। तीन लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपातकालीन सेवाओं ने बस से सभी को निकाल लिया है। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, जबकि अन्य को एक स्कूल सहित निकटवर्ती आश्रय स्थलों में ले

जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि विमान में सवार यात्री आठ विभिन्न देशों से हैं, जिनमें नॉर्वे, भारत, चीन, सिंगापुर, मलेशिया, नीदरलैंड, फ्रांस और दक्षिण सूडान शामिल हैं। नॉर्वे में चीनी दूतावास ने पुष्टि की है कि बस में करीब 20 चीनी पर्यटक सवार थे, जिनमें से पांच को मामूली चोट आई। दूतावास ने कहा कि वह पर्यटकों से संपर्क बनाए हुए है और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के

लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्रीय प्रसारक एनआरके से कहा, +मुझे लगता है कि कुछ भी हर कोई हैडसेल में जो कुछ भी सुन रहा है, उससे प्रभावित है। उन्होंने देश से उन लोगों के साथ खड़े होने का आग्रह किया जो बुरी तरह प्रभावित हैं। दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है।

